



भारत नरिवाचन आयोग

Last Updated: July 2022

नरिवाचन आयोग क्या है?

भारत नरिवाचन आयोग, जसि चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है।

यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव का संचालन करता है।

पृष्ठभूमि

- भारतीय संविधान का भाग 15 चुनावों से संबंधित है जसिमें चुनावों के संचालन के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है।
- चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी, 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी।
- संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 तक चुनाव आयोग और सदस्यों की शक्तियों, कार्य, कार्यकाल, पात्रता आदि से संबंधित हैं।

संविधान में चुनावों से संबंधित अनुच्छेद

324	चुनाव आयोग में चुनावों के लिये नहिंति दायित्व: अधीक्षण, नरिदेशन और नरियंत्रण।
325	धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति विशेष को मतदाता सूची में शामिल न करने और इनके आधार पर मतदान के लिये अयोग्य नहिं ठहराने का प्रावधान।
326	लोकसभा एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा के लिये नरिवाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा।
327	विधायिका द्वारा चुनाव के संबंध में संसद में कानून बनाने की शक्ति।
328	किसी राज्य के विधानमंडल को इसके चुनाव के लिये कानून बनाने की शक्ति।
329	चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप करने के लिये बार (BAR)

नरिवाचन आयोग की संरचना

- नरिवाचन आयोग में मूलतः केवल एक चुनाव आयुक्त का प्रावधान था, लेकिन राष्ट्रपति की एक अधिसूचना के ज़रिये 16 अक्टूबर, 1989 को इसे तीन सदस्यीय बना दिया गया।
- इसके बाद कुछ समय के लिये इसे एक सदस्यीय आयोग बना दिया गया और 1 अक्टूबर, 1993 को इसका तीन सदस्यीय आयोग वाला स्वरूप फिर से बहाल कर दिया गया। **तब से नरिवाचन आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्त होते हैं।**
- नरिवाचन आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है।**
- मुख्य नरिवाचन अधिकारी IAS रैंक का अधिकारी होता है, जसिकी नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा चुनाव आयुक्तों की नयुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है।
- इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (दोनों में से जो भी पहले हो) तक होता है।
- इनहें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं।
- मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान ही पद से हटाया जा सकता है।

हटाने की प्रक्रिया

- उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों, मुख्य चुनाव आयुक्त, नरियंत्रक और महालेखा परीक्षक को दुर्व्यवहार या पद के दुरुपयोग का आरोप सिद्ध होने पर या अक्षमता के आधार पर संसद द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के माध्यम से ही पद से हटाया जा सकता है।
- नषिकासन के लिये दो-तर्हीई सदस्यों के विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है और इसके लिये सदन के कुल सदस्यों का 50 प्रतिशत से अधिक मतदान

होना चाहिये।

- उपरोक्त पदों से किसी को हटाने के लिये संविधान में 'महाभयौग' शब्द का उपयोग नहीं किया गया है।
- महाभयौग शब्द का प्रयोग केवल राष्ट्रपति को हटाने के लिये किया जाता है जिसके लिये संसद के दोनों सदनों में उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या के दो-तर्हिई सदस्यों के वशिष बहुमत की आवश्यकता होती है और यह प्रक्रिया किसी अन्य मामले में नहीं अपनाई जाती।

नरिवाचन आयोग के कार्य

- चुनाव आयोग भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य वधिधानसभाओं, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव की संपूर्ण प्रक्रिया का अधीक्षण, नरिदेशन और नरियंत्रण करता है।
- इसका सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य आम चुनाव या उप-चुनाव कराने के लिये समय-समय पर चुनाव कार्यक्रम तय करना है।
- यह नरिवाचक नामावली (Voter List) तैयार करता है तथा मतदाता पहचान पत्र (EPIC) जारी करता है।
- यह मतदान एवं मतगणना केंद्रों के लिये स्थान, मतदाताओं के लिये मतदान केंद्र तय करना, मतदान एवं मतगणना केंद्रों में सभी प्रकार की आवश्यक व्यवस्थाएँ और अन्य संबद्ध कार्यों का प्रबंधन करता है।
- यह राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है उनसे संबंधित वधिवों को नपिटाने के साथ ही उन्हें चुनाव चहिन आवंटित करता है।
- नरिवाचन के बाद अयोग्य ठहराए जाने के मामले में आयोग के पास संसद और राज्य वधिधानसभाओं के सदस्यों की बैठक हेतु सलाहकार क्षेत्राधिकार भी है।
- यह राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिये चुनाव में 'आदर्श आचार संहिता' जारी करता है, ताकि कोई अनुचित कार्य न करे या सत्ता में मौजूद लोगों द्वारा शक्तियों का दुरुपयोग न किया जाए।
- यह सभी राजनीतिक दलों के लिये प्रत उम्मीदवार चुनाव अभियान खर्च की सीमा नरिधारित करता है और उसकी नगिरानी भी करता है।

भारत नरिवाचन आयोग (Election Commission of India) का महत्त्व

- यह वर्ष 1952 से राष्ट्रीय और राज्य स्तर के चुनावों का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। मतदान में लोगों की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये सक्रिय भूमिका निभाता है।
- राजनीतिक दलों को अनुशासित करने का कार्य करता है।
- संविधान में नहित मूल्यों को मानता है अर्थात् चुनाव में समानता, नषिपक्षता, स्वतंत्रता स्थापित करता है।
- वशिषसनीयता, नषिपक्षता, पारदर्शिता, अखंडता, जवाबदेही, स्वायत्तता और कुशलता के उच्चतम स्तर के साथ चुनाव आयोजित/संचालित करता है।
- मतदाता-केंद्रित और मतदाता-अनुकूल वातावरण की चुनावी प्रक्रिया में सभी पात्र नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करता है।
- चुनावी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों और सभी हतिधारकों के साथ संलग्न रहता है।
- हतिधारकों, मतदाताओं, राजनीतिक दलों, चुनाव अधिकारियों, उम्मीदवारों के बीच चुनावी प्रक्रिया और चुनावी शासन के बारे में जागरूकता पैदा करता है तथा देश की चुनाव प्रणाली के प्रत लोगों का वशिवास बढ़ाने और उसे मजबूती प्रदान करने का कार्य करता है।

चुनावी सुधारों पर नरिवाचन आयोग की सफिरशैं:

वर्ष 2020 में, ECI के अधिकारियों और राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारियों सहित नौ कार्यसमूहों ने चुनावी सुधारों पर अपनी मसौदा सफिरशैं प्रस्तुत की। सफिरशैं में शामिल हैं:

- नए मतदाताओं के पंजीकरण और पते में परिवर्तन सहित वभिन्न मतदाता सेवाओं के लिये सभी प्रपत्रों (Forms) को एक ही प्रपत्र से प्रतस्थापित करना।
 - कई संख्या में फॉर्म भ्रम पैदा करते हैं और प्रक्रिया में दक्षता को प्रभावित करते हैं।
- 17 वर्ष की आयु में सभी संभावित मतदाताओं के लिये स्कूल या कॉलेज स्तर पर ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा शुरू करना ताकि 18 वर्ष की आयु में पात्र होते ही उन्हें मतदाता सूची में नामांकित किया जा सके।
- ECI ने मतदाता के रूप में नामांकन के लिये एक वर्ष में चार कट-ऑफ तथियों की भी सफिरशि की है।
- मतदाताओं की सुविधा के लिये मतदाता पहचान पत्र - EPIC - का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव किया गया है।
- "वभिन्न मतदान वधियों की संभावना और व्यवहार्यता" की तलाश करने की भी सफिरशि की गई थी।
 - IIT-मद्रास, ECI के लिये आधार-संबद्ध रमिोट वोटिंग सिस्टम के लिये एक प्रोटोटाइप पर काम कर रहा है।
- राजनीतिक दलों के लिये की गई सफिरशैं में उम्मीदवारों के ऑनलाइन नामांकन और पार्टियों द्वारा अनुमत खर्च की एक सीमा तय करना शामिल था।
 - वर्तमान में, व्यक्तितगत उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार पर सीमित खर्च की अनुमति है।
- एक अन्य सफिरशि सोशल मीडिया और प्रटि मीडिया पर मतदान से पहले "48 घंटे की मौन अवधि" (Silence Period of 48 Hours) लगाने की थी।
 - मतदान से पहले पछिले 48 घंटों में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर प्रचार करना फलिहाल प्रतबिधित है।

चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021 के प्रस्ताव

- दिसंबर 2021 में **लोकसभा** ने **चुनाव कानून (संशोधन) अधिनियम, 2021** पारित किया। यह अधिनियम मतदाता सूची डेटा और मतदाता पहचान पत्र को आधार पारस्थितिकी तंत्र से जोड़ने का प्रयास करता है।
- अधिनियम की मुख्य विशेषताएँ:**
 - नरिवाचक नामावली का 'डी-डुप्लीकेशन':** यह **जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950** की धारा 23 में संशोधन का प्रावधान करता है, जिससे मतदाता सूची डेटा को आधार पारस्थितिकी तंत्र से जोड़ा जा सके।
 - इसका उद्देश्य विभिन्न स्थानों पर एक ही व्यक्ति के एकाधिक नामांकन को रोकना है।
 - इससे फर्जी वोटिंग और फर्जी मतों को रोकने में मदद मिलेगी।
 - यह लकिय विभाग से संबंधित व्यक्तिगत, लोक शिकायत और कानून तथा न्याय पर संसदीय स्थायी समिति की 105वीं रिपोर्ट के अनुरूप है।
 - मल्टीपल क्वालफाइंग डेट्स:** नागरिकों को 18 वर्ष की आयु में वोटिंग का अधिकार मिल जाता है। हालाँकि 18 वर्ष की आयु के बाद भी कई लोग मतदाता सूची से बाहर रह जाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि 1 जनवरी को क्वालफाइंग तारीख के रूप में माना जाता है।
 - अधिनियम के अनुसार, वोटिंग रोल को अपडेट करने के लिये चार क्वालफाइंग तारीखों की घोषणा की जाएगी, जिसमें जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के महीनों के पहले दिने 18 वर्ष के हो चुके लोगों को शामिल किया जाएगा।
 - लैंगिक तटस्थता लाना:** 'सेवा मतदाताओं की पत्नियों' के पंजीकरण की भाषा को अब 'जीवन साथी' से बदल दिया जाएगा। यह कानूनों को और अधिक "लिंग-तटस्थ" बना देगा।
 - सेवा मतदाता वे हैं जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं या इसके बाहर राज्य के सशस्त्र पुलिस बल में सेवारत हैं या भारत के बाहर तैनात सरकारी कर्मचारी हैं।

नरिवाचन आयोग के समक्ष प्रमुख चुनौतियाँ

- वर्षों से राजनीति में हिसा और चुनावी दुरभावनाओं के साथ कालेधन और आपराधिक तत्त्वों का बोलबाला बढ़ा है और इसके परिणामस्वरूप राजनीति का अपराधीकरण हुआ है। इनसे निपटना नरिवाचन आयोग के लिये एक बड़ी चुनौती है।
- राज्यों की सरकारों द्वारा सत्ता का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है, जिसके तहत कई बार चुनावों से पहले बड़े पैमाने पर प्रमुख पदों पर तैनात योग्य अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया जाता है।
- चुनाव के लिये सरकारी वाहनों और भवनों का उपयोग कर नरिवाचन आयोग की आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जाता है।
- नरिवाचन आयोग के पास राजनीतिक दलों को वनियमिति करने के लिये पर्याप्त शक्तियाँ नहीं हैं।
- किसी राजनीतिक दल के आंतरिक लोकतंत्र और पार्टी के वित्तीय वनियमन को सुनिश्चित करने की भी कोई शक्ति नरिवाचन आयोग के पास नहीं है।
- हालिया वर्षों में नरिवाचन आयोग की नष्पक्षता पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं और यह धारणा ज़ोर पकड़ रही है कि चुनाव आयोग कार्यपालिका के दबाव में काम कर रहा है।
- मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य दो आयुक्तों के चुनाव में प्रमुख संस्थागत कमियों में से एक है कम पारदर्शिता का होना, क्योंकि इनका चयन मौजूदा सरकार की पसंद पर आधारित होता है।
- इसके अलावा EVM में खराबी, हैक होने और वोट दर्ज न होने जैसे आरोपों से भी नरिवाचन आयोग के प्रति आम जनता के विश्वास में कमी आती है।
- वर्तमान समय में सत्ताधारी दल के पक्ष में नचिले स्तर पर नौकरशाही की मलीभगत के खिलाफ सतर्क रहने की आयोग के सामने बड़ी चुनौती है।
- आयोग के जनादेश और जनादेश का समर्थन करने वाली प्रक्रियाओं को और अधिक कानूनी समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता है।
- नैतिकता सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक है कि सक्षम और योग्य व्यक्ति उच्च पदों का दायित्व संभालें।
- नरिवाचन आयोग की नष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिये द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट में सफ़ारिश की गई थी कि लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में वपिष के नेता, कानून मंत्री और राज्यसभा के उपाध्यक्ष के साथ प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में बना कॉलेजियम मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष नाम प्रस्तावित करे।

(भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। वर्तमान में राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तथा अनूप चंद्र पांडेय चुनाव आयुक्त के पद पर कार्यरत हैं।)